EDITOR'S SCATVIEW

Manoj Kumar Madhavan

There are new elements emerging in the Satellite broadband arena. Plans are being firmed up by blue chip companies in India like Tatas who are planning to enter the Satellite broadband business. How does this augur for the broadband market in India? This definitely brings in a much-needed investment into this sector. The Tata group and Canadian satellite communications services provider Telesat along with Elon Musk's Starlink, Jeff Bezos's Project Kuiper and Sunil Bharti Mittal-backed One Web and reportedly Measat also planning will definitely revolutionise the Satellite broadband markets.

Indian Govt is also looking at a new-look draft space legislation, aimed at liberalizing the sector and promoting more private sector involvement.

And with the rollout of 5G technology in India, Indian market is set for interesting times ahead. These are the new emerging technologies which will spur growth in the CATV market.

Amazon's AWS Cloud Infrastructure is redefining cloud technologies along with Microsoft's Azure. People want to move towards cloud infrastructure and towards being IP and internet based. But there is also still a degree of head-scratching going on about precisely which is the best approach to take. But again, these are the other new emerging technologies of the future for the entertainment ecosystem.

Indian Broadcasting Foundation along with broadcasters like Star, Disney India, Sony Pictures Networks India (SPNI), ZEEL and Viacom18 have filed petitions challenging the Bombay High Court order in the New Tariff Order (NTO 2.0).

All of them have challenged the Bombay High Court's decision to grant more powers to the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) to regulate pricing and impose restriction on bouquet discounts if it is necessary in the larger 'public interest'. The HC has done so while relying on the Supreme Court's judgement on airwaves in the Ministry of Information & Broadcasting (MIB) vs Cricket Association of Bengal (CAB) matter. The broadcasters have also argued that the Bombay High Court has snatched away the fundamental rights of the broadcasters by allowing TRAI to impose restrictions in 'public interest'. The broadcasters have also challenged the provisions of amended tariff order (NTO 2.0) like bringing down MRP to Rs 12, imposing twin conditions, and placing restrictions on bouquet discounting.

This legal battle will be a long haul one, unless the Supreme Court comes out with a judgement swiftly. Stay tuned for further developments.

(Manoj Kumar Madhavan)

सैटेलाइट ब्रॉडबैंड क्षेत्र में नये तत्व उभर रहे हैं। भारत में टाटा जैसी ब्लू चिप कंपनियों द्वारा योजनायें बनायी जा रही हैं जो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड कारोबार में प्रवेश करने की योजना बना रही है। यह भारत में ब्रॉडबैंड बाजार के लिए कैसा शुभ संकेत है? यह निश्चित रूप से इस क्षेत्र के लिए बहुत आवश्यक निवेश को लायेगा। टाटा समूह और कनाडाई सैटेलाइट संचार सेवा प्रदाता टेलीसैट के साथ एलोन मास्क का स्टारलिंक, जेफ बेजोस का प्रोजेक्ट कुइपर और सुनील भारती मित्तल समर्थित वन वेब और कथित तौर पर मीआसेट की योजना भी निश्चित रूप से सैटेलाइट ब्रॉडबैंड बाजार में क्रांति लायेगी।

भारत सरकार इस क्षेत्र को उदार बनाने और अधिक निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतरिक्ष कानून के लिए एक नये मसौदे पर भी विचार कर रही है।

इसके साथ ही भारत में 5जी तकनीकी की प्रस्तुतिकरण के साथ भारतीय बाजार आगे दिलचस्प समय के लिए तैयार है। ये नयी उभरती हुई तकनीकियां हैं जो सीएटीवी बाजार में विकास को गति देंगी।

अमेजन का एडब्लूएस क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर माइक्रोसॉफ्ट के यूजर के साथ क्लाउड टेक्नोलॉजी को फिर से परिभाषित कर रहा है। लोग क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और आईपी और इंटरनेट आधारित होने की ओर बढ़ना चाहते हैं। लेकिन अभी इस बात पर काफी अधिक विचार-विमर्श किया जा रहा है कि इसे लेने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। लेकिन फिर, ये मनोरंजन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भविष्य की अन्य नयी उभरती तकनीकियां हैं।

इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन ने स्टार, डिज्नी इंडिया, सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया (एसपीएनआई), जेडईईएल और वायकॉम 18 जैसे प्रसारकों के साथ बंबई उच्च न्यायालय के नये टैरिफ आदेश (एनटीओ 2.0) को चुनौती देने वाली याचिकायें दायर की है।

उन सभी ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) को मूल्य निर्धारण को विनियमित करने के लिए और अधिक अधिकार दिया जाए, जिससे कि यदि 'सार्वजनिक हित' में आवश्यक हो तो बुके छूट पर प्रतिबंध लगाया जा सके। एचसी ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) बनाम क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (सीएबी) मामले में एयरवेव्स पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए ऐसा किया है। प्रसारकों ने यह भी तर्क दिया है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने ट्राई को 'जनहित में प्रतिबंध लगाने की अनुमति देकर प्रसारकों के मौलिक अधिकारों को छीन लिया है। प्रसारकों ने संशोधित टैरिफ आदेश (एनटीओ 2.0) के प्रावधानों को भी चुनौती दी है, जैसे एमआरपी को घटाकर 12 रुपये करना, दोहरी शर्तें लगाना और बुके डिस्काउंटिंग पर प्रतिबंध लगाना।

यह काफी समय तक चलने वाली कानूनी लड़ाई होगी, जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय तेजी से फैसला नहीं देता है। आगे की घटनाक्रम के लिए हमारे साथ बने रहें।

(Manoj Kumar Madhavan)